(ग) और (घ) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय योजना आयोग द्वारा आठवीं योजना के लिए गठित सड़क संबंधी कार्यदल से है, जिसने अगस्त, 1989 में अन्य बातों के साथ-साथ, 1990–95 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय और राज्य सैक्टर के सड़क विकास के लिए 32,630 करोड़ रु० के परिव्यय की सिफारिश की थी। तथापि, योजना आयोग ने आठवीं योजना (1992-97) में सड़कों के लिए लगभग 12,833 करोड़ रु० का परिव्यय निर्धारित किया है।

बसों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रयोग

1436. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 मई, 1992 के टाइम्स आंफ इंडिया में "सी० एन० जी० में रन बसिज" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो देश में परिवहन के क्षेत्र में संपीड़ित प्राकृतिक गैस के प्रयोग संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) सड़क परिवहन क्षेत्र में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी० एन० जी०) का उपयोग अभी प्रयोगिक स्तर पर है। प्रारम्भ में सी० एन० जी० का उपयोग मुख्यतः पैट्रोल से चलने वाले वाहनों में किया जाएगा क्योंकि वित्तीय रूप से सी०एन०जी० उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक होगी। पैट्रोलियम मंत्रालय ने प्रस्ताव का प्रथम चरण अनुमोदित कर दिया है जिसके अंतर्गत 220 पैट्रोल चालित वाहनों को प्रायोगिक तौर पर सी०एन०जी० से चलाया जाएगा।

मूल्य के कारण तथा तकनीकी आंकड़ों की अपर्याप्तता के कारण डीजल के स्थान पर सी०एन०जी० का प्रयोग करने के प्रश्न पर और तकनीकी-आर्थिक जांच करने की आवश्यकता है। इस वर्ष, दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की 5 बसों को प्रयोग के तौर पर सी० एन०जी० डीजल की दुहरी ईंधन विधि से चलाए जाने के लिए परिवर्तित किया जाएगा। मद्रास रिफाइनरीज लिए ने भी प्रयोग के तौर पर 10 बसों को परिवर्तित करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है तथा सी एन जी–डीजल दुहरी ईंधन विधि पर पहली बस ने 22–3–92 से प्रचालन शुरू कर दिया। छह और बसों को परिवर्तित कर दिया गया है और वे प्रचालन में हैं।

सड़क परिवहन क्षेत्र में सी एन जी के बड़े पैमाने पर उपयोग की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता, इन प्रयोगों के तकनीकी और आर्थिक परिणामों पर निर्भर करेगी।

Pending proposals of Andhra Pradesh

1437. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether any proposals have been received from the Government of Andhra Pradesh which are pending for approval;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) at what stage of consideration these proposals stand?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (c) A statement is annexed.

Statement

Position of the pending proposals in respect of National Highways, Central Road Fund and Inter-State or Economic Importance Scheme and New National Highways.

Statement

Position of the pending proposals in respect of National Highways, Central Road Fund and Inter-State or Economics Importance Scheme and New National Highways

No. of Pending proposals	Amount	Position
National Highways Roads - 6	Rs. 5.00 crores	Under consideration
Bridges - 2	Rs.333.84 lakhs	Under consideration
Central Road Fund-401	Rs. 298.27 crores	These schemes wil be considered for approval as and when the actual augumentation of CRF takes place.
E and I Scheme 15	Rs. 1071.00 lakhs	The decision on the proposals referred by various State Govts. including Andhra Pradesh in 8th Plan is expected to be taken or funding under E&I loan assistance programme in consultation with the appraising agencies. It is, therefore, not possible to indicate to what extent the proposals of Andhra Pradesh would be got accommodated in the above said programme
New National Highway		Various State Govts. have sent a total 135 proposals aggregating to approximately 37,566 kms. including the road in question in Andhra Pradesh, for declaration as New National Highways during the 8th Five Year Plan. In order to examine the proposals in detail with respect to the laid down criteria, the State Govts. were requested to send information about each proposal in a prescribed proforma bringing out the complete details/justification etc. This information is still awaited from a number of States. There is also paucity of resources As such it is too early to indicate decision about new National Highways in the 8th Plan including in Andhra Pradesh.